**झारखण्ड मुिक्त वािहनी की तरफ से जारी बयान**

ज्ञात हो िक िडमना बांध के िलए 1941 में िबहार के गवनर्रएवं िटस्को के बीच एक करार हुआ था िजसके आधार परजनिहत अथार्त कंपनी एवं नागिरक जरूरतों के िलए इस बांध

का िनमार्ण करना था बांध का िनमार्ण हुआ, शहर एवं कंपनी को पानी िमला, परन्तु 12 गांव के लोग उजड़ गये। चंद मुआवजे केसाथ वे पुश्तेनी घर बार छोड़ने को बाध्य हुए तब से ये ग्रामीण अपने पुनवार्स एवं मानवीय जीवन के हक के िलए संघषर् कर रहे हैं।

िपछले 6 वषर् से झारखण्ड मुिक्त वािहनी के बैनर तले पुनवार्स हक पाने का संघषर् जारी है। प्रशसन की मध्यस्थता से िवस्थािपतों एवंटाटा स्टील की 18 दौर की वातार् हो चुकी है। इस वातार् में यह तय हो चुका है िक लायलम एवं पुनसा ग्राम के 5.83 एकड़ ऐसी

जमीन डूब में आ रही है िजसका अिधग्रहण भी नहीं हुआ। न तो कोठ्र क्षितपूितर् दी गयी है और न ही िकराया। इस जमीन का टाटास्टील को क्या करना है यह भी िनणर्य नहीं िलया जा रहा है। टाटा स्टील रैयतों, वन-िवभाग एवं सरकारी 102 एकड़ जमीन पर 42 अवैध दखल की हुई थी। अिधग्रिहत इस जमीन की क्षितपूितर् देने के िलए कंपनी तैयार नहीं है।

हमारी मांगें -

टाटा कंपनी अितक्रिमत 102 एकड़ जमीन की क्षितपूितर् दी जाये।

िडमना बांध में अन-अिधग्रिहत मौजा पुनसा के 3.84 एकड़ और लायलम के 1.99 एकड़ जमीन के फसल के नुकसान की क्षितपूितर्

दे।

िडमना बांध के िवस्थािपतों को बकाया मुआवजा, नौकरी और पुनवार्स की व्यवस्था की जाय।

टाटा कंपनी के द्वारा िवस्थािपत पिरवारों को िडमना के पानी के उपयोिगता मूल्य या लाभ का आधा िहस्सा िदया जाए।

िडमना बांध में नौकाचालन और मत्स्य पालन का अिधकार िवस्थािपतों के समूह को िदया जाये।

टाटा स्टील के कमर्चािरयों की तरह िवस्थािपत पिरवारों को भी नौकरी, िचिकत्सा और िशक्षा की सुिवधायें दी जायें।

िडमना बांध के िकनारे अमरी पौधे की झािड़यो को िनयिमत रूप से साफ िकया जाये।

िडमना बांध के िकनारे-िकनारे िलफ्ट-इिरगेशन द्वारा िसंचाई की व्यवस्था की जाये।

कॉपोर्रेट सामािजक दाियत्व के तहत िवस्थािपत इलाको में ग्राम सभा की सहमित से िवकास कायर् िकया जाय।

िवस्थािपत मुआवजा एवं समुिचत पुनवार्स के साथ-साथ इस क्षेत्र में एक हाईस्कूल एवं िडस्पेन्सरी खोलने की मांग कर रहे हैं। मछली,

नौका पिरचालन पर िवस्थािपतों का हक कायम हो, कारपोरेट सामािजक दाियत्व को लगू िकया जाए और टाटा स्टील की नौकरी एवं

अप्रेिन्टस में प्राथिमकता दी जाए।

सत्याग्रह के समथर्कों के बैठने और इंतजाम की सामिग्रयों को रखने वाले दोनों टेंट िगर गये थे, िफर भी व्यवधान नहीं आने िदया गया। आज तो कल की अपेक्षा ज्यादा संख्या में जल सत्याग्रही पानी में उतरे, अथक खड़े रहे। आज मिहला सत्याग्रिहयों की भी संख्या ज्यादा रही। िवस्थािपत आंदोलनकारी िगरफ्ताररी देने के िलए पूरी तरह तैयार हैं। उल्लेखनीय है िक जल सत्याग्रह वैसे वक्त में हो रहा है, जब िडमना बांध में पुनसा और सायलम की 5.89 एकड़ जमीन गैर-अिधग्रिहत जमीन डूबी हुई है। लगभग 79 सालों से हर साल बरसात में लगभग इतनी जमीन डूबती है, िफर भी टाटा कंपनी क्षितपूितर्नहीं देती और न प्रशासन ही िटसको पर कोई कारर्वाई करता है। िडमना बांध टाटा घराने की बेईमानी और अनैितकता तथा प्रशासन

की संवेदनशून्यता और िनकम्मेपन का साक्ष्य बन चुका है। िपछले पांच-छः वषोर्ं से झारखंड मुिक्त वािहनी इस अनैितकता औरसंवेदनशून्यता के िखलाफ संघषर् करती आ रही है। यह आंदोलन इन मांगों की बुिनयाद पर िवकिसत हो रहा है- बांध में नौकापालन और मत्स्यपालन का अिधकार िवस्थािपतों को िमले। टाटा स्टील के मर्चािरयों की तरह िवस्थािपत पिरवारों को नौकरी, िशक्षा ओरिचिकत्सा की सुिवधा िमले। िवस्थािपतों के बकाया मुआवजा िमले। 102 एकड़ जमीन अिधग्रिहत करने के अपराध के िलए िटसको

को दंिडत िकया जाय और क्षितपूितर् वसूली जाय। िलफ्ट िसंचाई के जिरये बांध िकनारे के खेतों को िसंचाई की सुिवधा दी जाये।

िवस्थािपतों को पानी की उपयोिगता मूल्य और लाभ का िहस्सा िदया जाय।

आंदोलन के समथर्न में चांिडल बांध के िवस्थािपत नेता श्यामला माडीर्, िवस्थापन िवरोधी मंच के अग्रणी नेता कुमार चन्द्र माडीर्, डा.सोमाय, अरिवन्द अंजुम, कपूर बागी, घनश्याम, नारायण गोप ने भी सभा को संबोिधत िकया।

िवस्थािपतों की ओर से सबसे पहले िबना अिधग्रहण के डूब में आने वाली 5.83 एकड़ जमीन का मामला उठायां यह जमीन िडमना जलाशय के सामान्य स्तर पर ही प्रभािवत होती है िजसकामुआवजा िकसानों को िदया जाना चािहए। टाटा कंपनी की ओर से

िवस्थािपतों के दावे को नकारा गया और कहा िक 1971 से लेकरक अबतक 532 फुट तक पानी एक बार ही गया है। िवस्थािपत प्रितिनिधयों ने कहा िक यह जलाशय का जल स्तर नहीं है बिल्क ओवर-फ्लो का है। प्रितिनिधयों ने आग्रह िकया िक तथ्यों के आधार पर फैसला िकया जाय। इसके बाद िवस्थािपतों ने टाटा कंपनी द्वारा रैयतों का 17 एकड़ जमीन का मामला उठायां ज्ञात होिक वन िवभाग एवं सरकारी कुल 102 एकड़ जमीन पर टाटा ने न िसुर् अपना िपलर गाड़ कर कब्जा िकया बिल्क 1964 के नक्शे में इसे जलाशय का िहस्सा दशार्या गया। अवैध कब्जे की जमीन पर मुआवजे की मांग पर टाटा स्टील ने कहा िक उक्त जमीन पर उनका कोई दावा नहीं हैं इसके अलावा मछली पालन एवं नौका पिरचालन के मामले में भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं िनकला।

िवस्थािपतों ने इन मुद्दों पर टाटा स्टील के उच्च अिधकारी से िमलने का तय िकया। सामािजक उत्तरदाियत्व को पंचायत एवं ग्रामसभा के साथ िमलकर लागू करने की मांग की िजसे टाटा स्टील ने स्वीकार िकया।\_